Outstanding dues to the Hindustan Steel Ltd.

1706. SHRI R. R. MORARKA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what are the amounts due to the Hindustan Steel Ltd., from private parties as on the 31st March, 1978 and since when the same are outstanding;

(b) what are the reasons for which this amount has remained outstanding; and

(c) what are the names of the parties together with the amount due from each?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) As on 31st March, 1978, Rs. 8.87 crores were outstanding due to Hindustan Steel Limited from private parties to whom iron and steel materials were sold. Out of these Rs. 4.88 crores were pending for more than six months and 3.99 crores for less than six months.

(b) Most of the above outstandings are on account of credits extended to parties as an incentive for maintaining their normal off-take during the periods when the production of some categories of steel, particularly H. R. Coils and Skelp and Alloy Steels, was more than the domestic demand.

(c) It will not be in the commercial interest of the Company to disclose the amounts outstanding against individual parties.

ग्रामों में टेलीफोन की सुविधाओं सहित नये डाक तथा तार घरों का खोला जाना

1707. **श्री लाखन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड के गांवों में 1978 के दौरान कितने नये डाक तथा तारघर खोले जाने का विचार है तथा इनमें से कितने डाकघरों पर टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(ख) उस क्षेत्र में अब तक सरकार द्वारा कितने डाक तथा तारघर खोले गये हैं ?

†[**Opening of new Post and Telegraph offices with Telephone facilities in the villages**

1707. SHRI LAKHAN SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the number of new post and telegraph offices proposed to be opened during the year 1978 in the villages of Uttarakhand in Uttar Pradesh together with the number of post offices which will be provided with telephone facilities; and

(b) what is the number of post and telegraph offices Government have opened so far in that region?]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के गांवों में 137 नये डाकघर और 41 तारघर खोलने का प्रस्ताव है । सभी 41 तारघरों में टेलीफोन सुविधा दे दी जायेगी । प्रस्तावित 137 नये डाकघरों के खुल जाने के बाद उनमें टलीफोन सुविधायें देने के मामलों को गुणावगुण के आधार पर जांच की जायेगी ।

(ख) उत्तराखंड इलाके में जिसमें हल्द्वानी भी शामिल है, इस समय 1650 डाकघर और 267 तारघर काम कर रहे हैं । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तराखंड इलाके में अभी तक सात नये डाकघर खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है ।

†[ ]English translation.

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI NARHARI PRASAD SUKHDEO SAI): (a) It is proposed to open 137 new post offices and 41 telegraph offices in the villages of Uttarkhand in Uttar Pradesh during the year 1978. All the 41 telegraph offices will be provided with telephone facility. The cases for providing telephone facilities in the 137 new post offices proposed to be opened will be examined on merits after these post offices have been opened.

(b) There are at present 1650 post offices and 267 Telegraph offices functioning in the Uttarakhand area including Haldwani. Seven new post offices have been approved for opening in the Uttarakhand area so far in the current financial year.]

सरकारी क्षेत्र के समुपयोजन के लिए मध्य प्रदेश में चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों का आरक्षण

1708. श्री बलराम दास : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में चूने के पत्थर तथा बाक्साइट के प्रचुर भंडार वाले वृहत क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र द्वारा विदोहन किए जाने के लिए आरक्षित किया है; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने निकट भविष्य में इन क्षेत्रों में उपलब्ध भंडारों का विदोहन करने के लिए कोई योजना तैयार की है ?

†[Reservation of areas of lime-stone in M.P. for exploritation by the public sector

1708. SHRI BALRAM DAS: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have reserved large areas in Madhya Pradesh having rich deposits of lime-stone and bauxite for exploration by the public sector; if so, what are the details in this regard; and

(b) whether Government have formulated any scheme for the exploitation of the deposits available in these areas in the near future?]

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) मध्य प्रदेश के सतना, जबलपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर जिलों में चूना पत्थर वाले कुछ क्षेत्रों तथा शाहडोल, बिलासपुर, मांडला, सरगुजा और रायगढ़ जिलों तथा बालाघाट जिले की बेहड़ तहसील में बौक्साइट क्षेत्रों को क्रमश: सरकारी क्षेत्र के इस्पात व एल्यूमिनियम कारखानों की वर्तमान और भावी जरूरतों को ध्यान मे रखकर आरक्षित कर दिया गया है ।

(ख) मांडला, बिलासपुर तथा शाहडोल जिले के कुछ बौक्साइट निक्षेपों का भारत एल्यूमिनियम द्वारा अपने कोरबा प्रद्रावक में एल्यूमिनियम के उत्पादन हेतु पहले से ही उपयोग किया जा रहा है । सरगुजा निक्षेपों के बारे में रूसी सलहाकारों से एक विशाल निर्यात प्रधान एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, किन्तु परियोजना को उपयोगी न समझे जाने के कारण उसे चालू नही किया जा सका । इस जिले में और खोज कार्य चल रहा है । सतना जिले के कुछ बौक्साइट क्षेत्रों के संबंध में, जिन्हें पहले आरक्षित किया गया था, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि उन क्षेत्रों को आरक्षण से मुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है । जहां तक चूना पत्थर वाले क्षेत्रों का संबंध है वर्तमान इस्पात कारखानों की दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखकर आरक्षण करना होगा । मध्य प्रदेश के कुछ चूना पत्थर क्षेत्रों से पहले ही भिलाई, रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों को सप्लाई की जा रही है । आरक्षण की समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

†[ ] English translation.